(घ) क्या सरकार शुल्क की दरों को कम करके भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने का विचार रखती है;

(ङ) क्या यह भी सच है कि हमारे देश में आयात निर्यात शुल्क की दर अन्य देशों की तुलना में बहुत अधिक है; और

(च) यदि हां, तो उसे कम करने के लिए सरकार की क्या योजना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) जी हां। (ख) और (ग) विदेशी बाजारों में भारतीय माल के मूल्य न केवल आयात और निर्यात शुल्कों की दर पर निर्भर करते हैं बल्कि आधारभूत ढांचे की लागतों, प्रौद्योगिकी समावेशन, उत्पादक कार्यकुशलता, प्रचालन के तरों तथा साथ ही उत्पादों की गुणवत्ता तथा मानकीकरण, सुपुर्दगी की अनुसूची आदि जैसे मूल्य भिन्न कारकों पर भी निर्भर करते हैं। यात्री असबाब तथा एल्कोहाल वाले पेय पदार्थों को छोड़कर आयात शुल्क की अधिकतम दर (मूल + उपषंगी) 110 प्रतिशत है। निर्यात शुल्क की अधिकतम दर 15 प्रतिशत है।

(घ) से (च) सामान्य रुप में यह माना जाता है कि हमारी सीमाशुल्क टैरिफ दरें बहुत अधिक हैं और हमारे उन प्रतिस्पर्धी देशों में प्रचलित प्रवृत्तियों से बिल्कुल मेल नहीं खाती हैं जिन्होंने टैरिफों को बहुत साधारण स्तर तक कम कर दिया है। चेलैय्या समिति को सीमाशुल्कों के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए कहा गया था और उन्होंने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में टैरिफों के सामान्य स्तर में कमी करने की सिफारिश की है। यात्री असबाब तथा एल्कोहल वाले पेय पदार्थों को छोड़कर आयात शुल्कों (विशिष्ट शुल्क दरों सहित) की मूल + उपषंगी दर के शीर्ष टैरिफ स्तर में कमी करके इसको अधिकतम 110 प्रतिशत तक करते हुए इस वर्ष के बजट में इस दिशा में एक ठोस प्रयास किया गया है। परियोजना आयातों सहित पूंजीगत माल पर भी आयात शुल्क को कम कर दिया गया है।

जहां तक निर्यात शुल्कों का संबंध है, तैयार चमड़ा, प्रेनाइट तथा लौह अयस्क जैसी माल की केवल कुछेक मदों पर ही निर्यात शुल्क लगाया जाता है। इस संबंध में सरकार की नीति कतिपय मूल उत्पादों के निर्यातों पर कुछ प्रोत्साहनों को समाप्त करना है ताकि इनसे तैयार किये जाने वाले मूल्य वर्द्धित उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन दिया जा सके।

Subsidies On Food and Fertilizer

2958. SHRI SURENDRA SINGH THAKUR: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government had been providing subsidies on fertilizers and food grains to help promote agriculture; and

(b) if so, what subsidy has been provided in each items of food grain and fertiliser during last three year?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SHANTARAM POTDUKHE): (a) Fertiliser subsidy has *inter alia* encouraged larger fertiliser use by farmers. Food subsidy is a social security measure mainly meant for the poorer sections of the society.

(b) Food and fertilizer subsidies provided by the Government in the last three years are as follows.

(Rs. in crores)

	1988-89	1989-90	1990-91
Food:	2200.00	2476.00	2450.00
Fertilizer:			
(i) Indigenous	3000.00	3771.00	3729.73
Imported:			
(ii) Imported	200.00	771.00	659.33

News-item Captioned "Businessmen Dodge DRI's Net

2959. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a news item appearing in the Hindustan Times of the 20th February, 1992 captioned "Business dodge Directorate of Revenue Intelligence's Net";

(b) if so, what are the details thereof;

(c) whether any investigation has been conducted thereon; and

(d) what action has been taken against those found guilty?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) to (d) The Directorate of Revenue Intelligence is investigating alleged large scale misuse of the Duty Exemption Entitlement Scheme through the Land Customs Station, Tikonia on the Indo-Nepal Border, by some firms as reported in the Hindustan Times dated 20th February, 1992. Further investigations are still in progress.